

प्रेससूचनाब्यूरो

भारतसरकार

संसदमेंनागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 हुआपारित

**केंद्रीयगृहमंत्रीश्रीअमितशाहनेकहाकिइसबिलकाउद्देश्यधर्मकेआधारपर
पाकिस्तान,
अफगानिस्तानऔरबांग्लादेशकेप्रताड़ितअल्पसंख्यकोंकोसंरक्षितकरना
है, भारतकेअल्पसंख्यकोंकाइसबिलसेकोईलेना-देनानहींहै।**

**यहबिलसिर्फनागरिकतादेनेकेलिएहैकिसीकीनागरिकताछीननेकाअधि
कारइसबिलमेंनहींहै: केंद्रीयगृहमंत्री**

**आसामआंदोलनकेशहीदोंकीशहादतबेकारनहींजाएगी,
श्रीनरेंद्रमोदीसरकारपूर्वोत्तरकीभाषा,
संस्कृतिऔरसामाजिकपहचानकीरक्षाकेलिएप्रतिबद्धहै: केंद्रीयगृहमंत्री**

सीएबी (CAB)

**हमारेघोषणापत्रमेंथाऔरजनतानेविशालजनाधारदेकरइसकासमर्थनकि
याहै: श्रीअमितशाह**

**70 सालोंतकपाकिस्तान, बांग्लादेशऔरअफगानिस्तानसेआएवहां
केअल्पसंख्यकोंकोभगवानकेभरोसेछोड़दियागया: केंद्रीयगृहमंत्री**

**यदियहबिल50 सालपहलेआगयाहोतातोसमस्याइतनीबड़ीनहींहोती:
श्रीअमितशाह**

नईदिल्ली, 11 दिसंबर 2019

केंद्रीयगृहमंत्रीश्रीअमितशाहनेराज्यसभामेंनागरिकता (संशोधन) विधेयक2019 परबोलतेहुएकहाकियहबिलकरोड़ोंलोगोंकोसम्मानकेसाथजीनेकाअवसरप्रदानकरेगा।
उनकाकहनाथाकिपाकिस्तान,

बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है ।
उनका कहना था कि इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी कमी हुई है,
वह लोग या तो मार दिए गए,
उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया या वेशरणार्थी बन कर भारत में आए ।
श्री शाह ने कहा कि तीनों देशों से आए धर्म के आधार पर प्रताड़ित ऐसे लोगों को संरक्षित करना इस बिल
लका उद्देश्य है, भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई लेना-
देना नहीं है। राज्य सभामें विधेयक का परिचय देते हुए श्री शाह ने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य उन
लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है जो दशकों से पीड़ित थे।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश का बंटवारा और बंटवारे के बाद की स्थितियों के कारण यह
बिल लाना पड़ा। उनका कहना था कि 70
सालों तक देश को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। श्री नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने
के लिए नहीं आई है देश को सुधारने के लिए और देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आई
है। श्री शाह ने कहा कि हमारे पास 5
साल का बहुमत था, हम भी सत्ता का केवल भोग कर सकते थे किंतु देश की समस्या को कितने सालों
तक लटका कर रखा जाए, समस्याओं को कितना कितना बड़ा किया जाये। उन्होंने विपक्षी सांसदों
से कहा कि अपनी आत्मा के साथ संवाद करिए और यह सोचिए कि यदि यह बिल 50
साल पहले आ गया होता तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती।

श्री अमित शाह का कहना था कि 2019
के घोषणापत्र में असंदिग्ध रूप से इस बात की घोषणा की गई थी और यह इरादा जनता के समक्ष
खा गया था कि पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीएबीलागू करेंगे,
जिसका समर्थन जनताने किया है ।
श्री शाह का कहना था कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ यह सब से बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा
हाकि 8 अप्रैल 1950 को नेहरू-
लियाकत समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है,
में यह वादा किया गया था कि दोनों देश अपने-
अपने अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखेंगे किंतु पाकिस्तान में इसे अमल में नहीं लाया गया। भार
त ने यह वादा निभाया और यहां के अल्पसंख्यक सम्मान के साथ देश के सर्वोच्च पदों पर काम करने
में सफल हुए किंतु तीनों पड़ोसी देशों ने इस वादे को नहीं निभाया और यहां के अल्पसंख्यकों को प्रता
ड़ित किया गया।

एक प्रश्न के जवाब में श्री शाह ने कहा कि नागरिकता बिल में पहले भी संशोधन हुए और विभि
न्न देशों को उस समय की समस्या के आधार पर प्राथमिकता दी गई और यहां के लोगों को नागरिकता

प्रदानकीगई। आजभारतकीभूमि-सीमासेजुड़ेहुएइन3 देशोंकेलघुमती
(अल्पसंख्यक)शरणलेनेआएहैंइसलिएइन3 देशोंकीसमस्याकाजिक्रकियाजारहाहै।

श्रीशाहकाकहनाथाकिपासपोर्ट,
वीजाकेबगैरजोप्रवासीभारतमेंआएहैंउन्हेंअवैधप्रवासीमानाजाताहैकिंतुइसबिलकेपासहोने
केबादतीनोंदेशोंकेअल्पसंख्यकोंकोअवैधप्रवासीनहींमानाजाएगा |
श्रीशाहनेकहाकियहबिलभारतकेअल्पसंख्यकसमुदायकोलक्षितनहींकरताहै। धार्मिकउत्पी
ड़नकेशिकारइनतीनोंदेशोंकेलोगरजिस्ट्रेशनकराकरभारतकीनागरिकतालेपाएंगे |
श्रीशाहकाकहनाथाकि 1955 कीधारा 5
यातीसरेशेडयूलकीशर्तेंपूरीकरनेकेबादजोशरणार्थीआएहैंउन्हेंउसीतिथिसेनागरिकतादीजा
एगीजबसेवहयहांआएतथाइसबिलकेपासहोनेकेबादउनकेऊपरसेघुसपैठयाअवैधनागरिक
ताकेकेसस्वतःहीसमाप्तहोजाएंगे |
श्रीशाहनेकहाकिअगरइनअल्पसंख्यकोंकेपासपोर्टऔरवीजासमाप्तहोगएहैं,
तोभीउन्हेंअवैधनहींमानाजाएगा।

उन्होंनेकहाकिश्रीनरेंद्रमोदीसरकारपूर्वोत्तरराज्योंकीभाषाई,
सांस्कृतिकऔरसामाजिकहितोंकीरक्षाकेलिएप्रतिबद्धहैं।श्रीशाहनेकहाकिअधिनियमकेसं
शोधनोंकेप्रावधानअसम, मेघालय,
मिजोरमयात्रिपुराकेआदिवासीक्षेत्रपरलागूनहींहोंगेक्योंकिसंविधानकीछठीअनुसूचीमेंशामि
लहैंऔरपूर्वीबंगालकेतहतअधिसूचित 'इनरलाइन'
केतहतआनेवालेक्षेत्रकोकवरकियागयाहै। एकमहत्वपूर्णघोषणाकरतेहुएश्रीशाहनेकहाकिम
णिपुरकोइनरलाइनपरमित (ILP)
शासनकेतहतलायाजाएगाऔरइसकेसाथहीसिक्किमसहितसभीउत्तरपूर्वीराज्योंकीसमस्या
ओंकाध्यानरखाजाएगा।

श्रीअमितशाहनेआसामकाविशेषउल्लेखकरतेहुएकहाकिआसामआंदोलनकेशही
दोंकीशहादतबेकारनहींजाएगी | उनकाकहनाथाकि1985
मेंश्रीराजीवगांधीकेद्वाराक्लॉज़सिक्सकेतहतएककमेटीबनानेकानिर्णयलियागयाथाजोवहांके
लोगोंकीभाषा, संस्कृतिऔरसामाजिकपहचानकीरक्षाकरतीकिंतुयहआश्चर्यजनकबातहैकि
1985 सेलेकर 2014
तकतीनदशकोंसेज्यादासमयबीतजानेकेबादभीवहकमेटीहीनहींबनसकी |
उनकाकहनाथाकि2014
मेंश्रीनरेंद्रमोदीकीसरकारबननेकेबादउसकमेटीकागठनकियागया |
उन्होंनेआसामकेलोगोंसेआग्रहकियाकिवहसमझौतेकेप्रावधानोंकोपूराकरनेकेलिएप्रभावी
कदमउठानेकेलिएजल्दसेजल्दअपनीरिपोर्टकेंद्रसरकारकोसौंपे।उत्तर-

पूर्वीक्षेत्रोंकेलोगोंकीआशंकाओंकोदूरकरतेहुएगृहमंत्रीनेकहाकिक्षेत्रकेलोगोंकीभाषाई, सांस्कृतिकऔरसामाजिकपहचानकोसंरक्षितरखाजाएगाऔरइसविधेयकमेंसंशोधनकेरूप मेंइनराज्योंकेलोगोंकीसमस्याओंकासमाधानहै।पिछलेएकमहीनेसेनॉर्थईस्टकेविभिन्नहित धारकोंकेसाथमैराथनविचार-

विमर्शकेबादशामिलकियागयाहै।उन्होंनेकहाकिइसमुद्देकोराजनीतिकविचारधाराओंसेपरे एकमानवतावादीकेरूपमेंदेखाजानाचाहिए।

केंद्रीयगृहमंत्रीनेकहाकिइसविधेयकमेंऐसेशरणार्थियोंकोउचितआधारपरनागरिक ताप्रदानकरनेकेप्रावधानहैं,

जोकिसीभीतरहसेभारतकेसंविधानकेतहतकिसीभीप्रावधानकेखिलाफनहींजातेहैंऔरअनुच्छेद

14

काउल्लंघननहींकरतेहैं।श्रीशाहनेयहभीकहाकिदेशकेसभीअल्पसंख्यकोंकोविश्वासदिलाना चाहताहूँकिश्रीनरेंद्रमोदीसरकारकेहोतेहुएइसदेशमेंकिसीभीधर्मकेनागरिककोडरनेकीजरूरतनहींहै, यहसरकारसभीकोसुरक्षाऔरसमानअधिकारदेनेकेलिएप्रतिबद्धहै।

श्रीअमितशाहनेएकसदस्यकेप्रश्नकेजवाबमेंकहाकिहमचुनावीराजनीतिअपनेदेशके नेताकेदमपरकरतेहैंऔरउसमेंसफलहोतेहैंकिंतुदेशकीसमस्याकासमाधानकरतेसमयपूरा ध्यानसमस्यापरकेंद्रितहोता।

श्रीअमितशाहनेकहाकिमोदीजीकेशासनकालमेंपिछले5 वर्षोंमें566 सेज्यादामुस्लिमोंकोभारतकीनागरिकतादीगई।श्रीशाहनेकहाकियहबिलसिर्फनागरिकतादेनेकेलिएहैकिसीकीनागरिकताछीननेकाअधिकारइसबिलमेंनहींहै।उनकाकहनाथाकिश्रीनरेंद्रमोदीसरकारमानतीहैकिजिनकीप्रताड़नाहुईहै,उनसबकीमददसरकारकोकरनीचाहिए।

एसएनसी / डॉडीडी